

2249/XVII/(2)2010

प्रषक,

सुभाष कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,

दिनांक:

11

नवम्बर, 2010

विषय:- वाद संख्या 666/1992 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति प्रथम अपीलीय समिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वाद संख्या 666/1992 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अनुपालन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या 2840/XVII(2)/05-90/2005 दिनांक 22 अगस्त 2005 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की संस्तुति करने के लिये जनपद स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया था। उक्त शासनादेश को संशोधित करते हुये जनपद स्तरीय समिति निम्नानुसार प्रथम अपीलीय समिति होगी-

- |   |            |
|---|------------|
| 1-जिलाधिकारी  | अध्यक्ष    |
| 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक  | सदस्य      |
| 3-जनपद की वरिष्ठ महिला चिकित्साधिकारी   | सदस्य      |
| 4-जनपदस्तरीय कार्यालयों की 02 महिला कार्यालयाध्यक्ष   | सदस्य      |
| 5-जिला शासकीय अधिवक्ता  | सदस्य      |
| 6-जिलाधिकारी द्वारा नामित 02 स्वैच्छिक संगठन की महिला सदस्य (महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में कार्यरत) | सदस्य      |
| 7-जिला समाज कल्याण अधिकारी  | सदस्य      |
| 8-जिला कार्यक्रम अधिकारी  | सदस्य-सचिव |

2. उक्त समिति में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। यह समिति जनपद में राज्य सरकार के अधीन समस्त कार्यालयों, निजी संस्थाओं आदि के लिये "प्रथम अपीलीय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" के रूप में कार्य करेगी। स्वैच्छिक संगठन से नामित सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्ष होगा। तीन वर्ष बाद अध्यक्ष द्वारा स्वैच्छिक संगठनों से समिति के नये सदस्य नामित किये जायेंगे। स्वैच्छिक संगठन से नामित सदस्यों को समिति की बैठक में प्रतिभाग करने के लिये मानदेय, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।



3. जिलाधिकारी अपने जनपद में स्थापित समस्त जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों/बैंको में (यदि पूर्व से गठित न हों) "आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति" का गठन सुनिश्चित करेंगे। समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 05 सदस्य होंगे जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी। समिति की अध्यक्ष वरिष्ठतम महिला अधिकारी/कार्मिक होगी। समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में सम्बन्धित कार्यालयों के विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों के कार्मिकों को भी नामित किया जा सकता है। यह समिति विभागीय आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति कहलाएगी। इस समिति की कार्य प्रक्रिया आदि का निर्धारण वाद संख्या 666/1992 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अगस्त 1997 के अधीन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. निजी संस्थाएँ/स्वयंसेवी संस्थाएँ जहां 05 से अधिक महिला कार्मिक हैं, वहां भी सरकारी कार्यालयों की भांति उपरोक्तानुसार समितियों का गठन किया जायेगा। जहां 05 से कम महिला कार्मिक हैं वहां उन्हीं में से किसी एक महिला कार्मिक को सलाहकार के रूप में नामित/उद्घोषित किया जायेगा। यह महिला सलाहकार उनको प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच करते हुए जांच आख्या जिला स्तरीय यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण समिति के संज्ञानार्थ प्रेषित करेंगी जिस पर अग्रिम कार्यवाही करने पर जिला स्तरीय समिति निर्णय लेगी। निजी संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरणों पर यदि जनपद स्तरीय अपीलीय समिति के विरुद्ध अपील की जानी होगी तो यह प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

5. "आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" प्राप्त शिकायतों की जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी। जांच के उपरान्त अपनी संस्तुति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "प्रथम अपीलीय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" को प्रेषित करेंगी। प्रथम अपीलीय समिति जांच का समुचित परीक्षण करेगी, यदि शिकायत सही प्रतीत होती है तो सम्बन्धित को दोषी मानते हुये दण्ड की अनुसंशा सम्बन्धित विभाग/संस्था/उपक्रम/बैंक आदि के नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/दण्डाधिकारी/उच्चाधिकारी (जिसके अधीन दण्ड दिये जाने का प्राधिकार निहित हो) को करेगी। समिति की संस्तुति के आधार पर सम्बन्धित विभाग/संस्था/उपक्रम/बैंक आदि के नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/दण्डाधिकारी/उच्चाधिकारी (जिसके अधीन दण्ड दिये जाने का प्राधिकार निहित हो) द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना प्रथम अपीलीय समिति को देनी होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें विभागाध्यक्ष के विरुद्ध उत्पीड़न की शिकायत की गई हो, राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।


6. प्रथम अपीलीय समिति द्वारा बिन्दु संख्या 5 के अनुसार की गई कार्यवाही/अनुसंशा की सूचना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड एवं राज्यस्तरीय "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" को प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम अपीलीय समिति अपने विवेकानुसार किसी प्रकरण को राज्यस्तरीय कार्यस्थल पर "यौन उत्पीड़न निवारण समिति" को भी संदर्भित कर सकती है।

7. प्रथम अपीलीय समिति के निर्णय के विरुद्ध एक माह के अन्दर राज्य स्तरीय "आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" को अपील की जा सकती है।

8. जनपद स्तरीय एवं "आन्तरिक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति" के गठन का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा। समिति की बैठक त्रैमासिक अवधि में (जून, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च) में आयोजित की जायेगी तथा प्राप्त शिकायतों की सूचना उनके निस्तारण, की स्थिति एवं संस्तुति सहित कार्यवृत्त का विवरण राज्यस्तरीय "आन्तरिक कार्यस्थल पर "यौन उत्पीड़न निवारण समिति" एवं निदेशालय आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(सुभाष कुमार)  
मुख्य सचिव

संख्या : 2249 / XVII(2) / 2010, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति / प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायू मण्डल नैनीताल।
- 3- निदेशक आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
- 5- सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त जिलास्तरीय कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)  
सचिव